SHRI AMAR SINGH: Sir, I would like to know from the hon. Minister what is the component of cess in the price per litre of petrol and other products. What is the amount collected so far by way of cess? Is there any proposal to withdraw the cess?

SHRI MURLI DEORA: You should put that question to the hon. Finance Minister, not to me.

MR. CHAIRMAN: The Finance Minister is also here. Next Question.

SHRI MURLI DEORA: So, this question can be transferred.

*44. *[The questioner (Shri Pramod Mahajan) was absent. For answer vide page 32.]*

हिमालयी क्षेत्र में गैस और तेल की खोज

*45. **श्री कृपाल परमार:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार का ध्यान अब हिमालय में गैस एवं तेल की खोज की तरफ गया है क्योंकि इस क्षेत्र से मिले आंकड़ों के विश्लेषण से वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वहां पेट्रोल-एवं गैस मिलने की संभावनाएं प्रबल हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उस पर कितना व्यय होगा और यह कितने वर्ष का कार्यक्रम है और कब तक सफलता मिलने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा): (क) से (ख) सदन के पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) हिमालयी क्षेत्र में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के लिए अन्वेषण आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) की स्थापना के बाद से विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश राज्य में 1956 में आरंभ हुआ। संपूर्ण हिमालय तराई क्षेत्र, सुन्दर नगर के पास चौमुखा में ज्ञात सतही तेल प्रदर्शनों और ज्वालाजी मंदिर, ज्वालामुखी के पास ऐतिहासिक गैस प्रदर्शनों के कारण सक्रिय अन्वेषण के अंतर्गत रहे हैं।

स्थापना के बाद से ओएनजीसी ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब और उत्तर प्रदेश राज्य में आने वाले हिमालय की तराई क्षेत्र में 8,198 ग्राउंड लाइन किलोमीटर (जीएलके) द्विआयामी भूकंपीय आंकड़े प्राप्त किए हैं और 19 कूपों का वेधन किया है। तथापि, अभी तक कोई वाणिज्यिक सफलता हाथ नहीं लगी है। दसवीं योजनावधि के दौरान ओएनजीसी ने इस क्षेत्र

में 225 जीएलके द्विआयामी भूकंपीय आंकड़े प्राप्त करने और तीन अन्वेषणात्मक कूपों का वेधन करने की योजना बनाई थी। ओएनजीसी ने हिमाचल प्रदेश में पहले ही 605 जीएलके द्विआयामी भूकंपीय आंकड़े प्राप्त किए हैं और दो अन्वेषणात्मक कूपों का वेधन किया है। आयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) ने भी उत्तरांचल में हिमालय की तराई में लगभग 2786 जीएलके द्विआयामी भूकंपीय आंकड़े प्राप्त किए हैं। अन्वेषण प्रयासों को अनुपूरित करने के लिए हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) ने भी हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्य में आने वाले 24,000 किलोमीटर वायुचुम्बकीय सर्वेक्षण आंकड़े प्राप्त किए हैं।

नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी)के तीसरे दौर के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में प्रदान किए गए ब्लाक एचएफ-ओएनएन-2001/1 में अन्वेषण के दूसरे चरण के दौरान ओएनजीसी को 60 जीएलके द्विआयामी आंकड़े प्राप्त करने और एक अन्वेषणात्मक कूप का वेधन करने की योजना है। ओआईएल की उत्तरांचल में एक अन्वेषणात्मक कूप का वेधन करने की योजना है।

हिमाचल प्रदेश में ओएनजीसी और उत्तरांचल में ओआईएल द्वारा अन्वेषण कार्यों पर योजित निवेश क्रमश: 45 करोड़ रुपए और 35 करोड़ रुपए है।

हाइड्रोकार्बन अन्वेषण एक उच्च जोखिम वाला और उच्च पुरस्कार वाला कार्य है जिसमें अन्वेषणात्मक निवेश निर्धारणीय रहते हैं, वहीं खोजों के संबंध में परिणाम अत्यंत संभावनायुक्त होते हैं और इसलिए अन्वेषण प्रयासों की सफलता का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता।

Exploration of gas and oil in himalayan region

†*45. SHRI KRIPAL PARMAR: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have now turned its attention towards exploring gas and oil reserve in Himalayan region as scientists have arrived at a conclusion after analyzing data from the region that there is a great possibility of stricking petrol and gas therein; and

(b) if so, the details thereof indicating the expenditure likely to be incurred on the same and the duration of the said programme and by when, success is likely to be achieved?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI MURLI DEORA): (a) to (b) A Statement is laid on the Table of the House.

† Original notice of the question was received in Hindi.

Statement

(a) and (b) Exploration for crude oil and natural gas in the Himalayan region started as early as 1956 especially in the State of Himachal Pradesh soon after the inception of Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC). The entire Himalayan foothills have remained under active exploration because of known surface oil shows at Choumukha near Sundernagar and historical gas show near Jwalaji temple, Jwalamukhi.

Since inception, ONGC has acquired 8,198 Ground Line Kilometres (GLK) of 2D seismic data and frilled 19 wells in the Himalayan foothills region falling in the State of Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Punjab and Uttar Pradesh. However, there has not been any commercial success so far. During Tenth Plan period, ONGC envisaged to acquire 225 GLK 2D seismic data and drill three exploratory wells in the region. ONGC has already acquired 605 GLK of 2D seismic data and drilled two exploratory wells in Himachal Pradesh. Oil India Limited (OIL) has also acquired about 2,786 GLK of 2D seismic data in Himalayan Foothills in Uttaranchal. To supplement the exploration efforts, Directorate General of Hydrocarbons (DGH) has also acquired 24,000 Kilometres of aeromagnetic survey data falling in the State of Himachal Pradesh and Punjab.

During second phase of exploration in the block HF-ONN-200/1 in Himachal Pradesh awarded under the third round of New Exploration Licensing Policy (NELP), ONGC plans to acquire 60 GLK of 2D seismic and drill one exploratory well. OIL plans to drill one exploratory well in Uttaranchal.

The planned investment on exploration activities by ONGC in Himachal Pradesh and OIL in Uttaranchal is about Rs. 45 crore and Rs. 35 crore respectively.

Hydrocarbon exploration is a high rise and high reward activity; in which while exploratory inputs remain determinable, results in terms of discoveries are highly probabilistic and therefore success of exploration efforts can not be predicted.

श्री कृपाल परमार: माननीय सभापति महोदय, जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि कृष्णा-गोदावरी और राजस्थान तथा गुजरात में तेल के पर्याप्त भंडार मिलने के बाद हिमाचल एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सर्वेक्षणों के द्वारा सरकार के पास जानकारी है कि दुनिया के सबसे बड़े तेल

के भंडार और प्राकृतिक गैस के भंडार वहां होने की संभावना है। माननीय मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्य में आने वाले 24,000 किलोमीटर वायु चुम्बकीय सर्वेक्षण आंकड़े प्राप्त किए हैं, जो इस बात का संकेत देते हैं कि वहां पर बहुत बड़े भंडार होने की संभावना है।

माननीय सभापति महोदय, जब से ONGC का गठन हुआ है, तब से हिमाचल प्रदेश में लगातार तेल की खोज का काम चल रहा है, लेकिन वहां पर कभी भी गंभीरता से प्रयास नहीं हुआ और इसका प्रमाण यह है कि हिमाचल प्रदेश में ONGC ने अन्वेषण के कार्यों पर योजित निवेश क्रमश: 45 करोड़ रुपया खर्च करने की योजना बनाई है। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि अगर हिमालय में गंभीरता से तेल की खोज का प्रयास करना है, तो ONGC का मानना है कि वहां पर अगर एकमुश्त पांच सौ करोड़ रुपया निवेश किया जाए, तो वहां पर तेल की गहराई तक पहुंचा जा सकता है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या हिमालय के क्षेत्र में तेल की खोज के लिए पांच सौ करोड़ रुपए का प्रावधान करके उस क्षेत्र में तेल खोजने का प्रयास करेंगे?

श्री मुरली देवरा: सम्मानित सदस्य ठीक कह रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके लिए और प्रावधान करें, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ONGC has acquired 8,198 Ground Line Kilometres of 2D seismic data and drilled in 19 wells in the Himalayan foothills region falling in the States of Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Punjab and Uttar Pradesh. However, there has not been any commercial success so far. इसकी कोशिश की जा रही है कि पैसे का प्रावधान और बढ़ाया जाए।

श्री कृपाल परमार: माननीय सभापति महोदय, वर्षों पहले ज्वालामुखी के पास बग्गी के क्षेत्र में एक कुएं की खुदाई की गई थी जिसको बाद में बंद कर दिया गया। दो वर्ष पूर्व वह नलकूप एक भयंकर विस्फोट के बाद खुल गया था और वहां पर कच्चे तेल और गैस का रिसाव शुरू हुआ। देहरादून से ONGC के अधिकारियों ने जाकर उसको बंद किया था। यह इस बात का प्रमाण है कि उस क्षेत्र में गैस की अपार संभावनाएं हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ज्वालामुखी के क्षेत्र में फिर से खोज का कार्य क्या आरंभ किया जाएगा?

श्री मुरली देवरा: यह कोशिश की जा रही है, लेकिन कॉमर्शियल लेवल पर वहां गैस और ऑयल नहीं मिला है, लेकिन कोशिश की जा रही है।

SHRI P.G. NARAYANAN: Mr. Chairman, Sir, ONGC and private players have discovered massive gas reserves in Krishna Godavari Basin recently. Will the Government take up deep water drilling in the adjacent Cauvery Basin immediately?

SHRI MURLI DEORA: I don't have this information now, but I will send you a reply after some time.

श्री रुद्रनारायण पाणि: सभापति महोदय, जून, 2004 से हर मामले में उड़ीसा के प्रति भेदभाव किया जा रहा है। ऑयल इंडिया लिमिटेड की एक शाखा भुवनेश्वर में है, जिसमें लगभग 35 कर्मचारी काम करते हैं, दो मैनेजर डायरेक्टर स्तर के हैं। उस शाखा को वहां से हटाने की साजिश हो रही है। क्या मंत्री जी उसके बारे में कुछ बता सकते हैं?

श्री सभापति: क्या मंत्री जी उस साजिश में शामिल हैं?

श्री रुद्रनारायण पाणि: सर, वह तो आप बताएंगे, मंत्री जी बताएंगे या प्रधान मंत्री बताएंगे।

श्री मुरली देवरा: सर, आपने ठीक कहा, मैं उस साजिश में शामिल नहीं हूं।

श्री रुद्रनारायण पाणि: नहीं सर, मंत्री जी साजिश में तो शामिल नहीं हैं। मैं यह आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन उस शाखा को वहां से हटाने की बात है। वहां के कर्मचारी कहते हैं कि उनको काम नहीं दिया जाता है। जो काम कर्मचारी करते हैं, मैनेजर लेवल पर sabotage होता है।

श्री सभापति: ठीक है, ठीक है, हो गया है। ...(व्यवधान)...

श्री रुद्रनारायण पाणि: सर, अभी 34 कर्मचारी हैं, उनमें से 14 कर्मचारियों को स्थानांतरित करने का आदेश दे दिया गया है। 34 में से 14 ट्रांसफर होंगे। सर, उल्फा ग्रसित क्षेत्र में उड़िया लोगों को ट्रांसफर करते हैं, ताकि वे न जाएं, इस प्रकार की साजिश हो रही है।

श्री सभापति: अब हो गया आपका क्वेश्चन ...(व्यवधान)...

श्री रुद्रनारायण पाणि: सर, मैं ऑयल इंडिया लिमिटेड की भुवनेश्वर शाखा के बारे में पूछ रहा हूं।

श्री सभापति: मंत्री जी, आप कुछ बोलेंगे? उड़िया लोगों को आप दूसरी जगह भेज रहे हैं।

श्री मुरली देवरा: सर, मुझे कहा गया है कि यह ऑफिस क्लोज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको इसकी पूरी जानकारी बाद में दे दूंगा।

श्री लेखराज बचानी: सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि देश में जो पेट्रो फ्यूल की शार्टेज है, उसका अल्टरनेटिव तरीका बॉयोगैस टैक्नॉलोजी से प्रोडक्शन बढ़ाना है। देश की कितनी स्टेटों में ऐसे एग्रीकल्चर प्लांट्स लग रहे हैं, इनके बारे में गवर्नमेंट ने क्या स्कीम बनाई है और बॉयोगैस टैक्नॉलोजी से कितना फ्यूल देश को मिल सकता है? ONGC ने गुजरात में जो पहले 8 वैल्स ड्रिल किए थे वे छोड़ दिए थे, गुजरात के पैट्रोलियम एक्विजिशन बोर्ड ने अहमदाबाद जिले में धनुरका के पास बहुत सक्सेसफुली एक ऑयल वैल को ड्रिल किया। गुजरात गवर्नमेंट का दावा है कि वहां से बहुत तेल मिलेगा। गुजरात में जो बाकी सात

ऑयल वैल्स ONGC ने छोड़े हैं और गुजरात के उस कारपोरेशन ने वहां फिर एक्सप्लोरेशन शुरू करने के लिए जो डिमांड की है, उसके बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है?

श्री मुरली देवरा: पहला जो आपने बॉयोगैस के बारे में सुझाव दिया है, इसके लिए अलग से क्वेश्चन चाहिए, लेकिन मैं इसके लिए आपको जवाब दूंगा कि इस बारे में सरकार क्या कर रही है? दूसरा आपने गुजरात के बारे में कहा है तो मुझे इस समय इसके बारे में जानकारी नहीं है। मैं आपको इसका लिखित में जवाब दे दूंगा।

Lower interest rate on loans to farmers

*46. SHRI JANARDHANA POOJARY: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether banks are mandated to advance loans to farmers/ artisans, including Self-Help Groups, at reduced rate of interest;

(b) whether certain banks have not even made a single such advance;

(c) if so, the details thereof;

(d) whether it is a fact that loans for cars and other luxury items are freely extended by the banks at rates lower than the rate at which the loan is extended, if any, to the farmers and other poor customers; and

(e) if so, the details thereof and the action taken to ensure proper distribution of loans to the farmers at reduced rate of interest?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) to (e) A Statement is laid on the Table on the House.

Statement

(a), (d) and (e) As per guidelines of Reserve Bank of India, domestic scheduled commercial banks are mandated to lend to the priority sector (including to agriculture, weaker sections, SSI, etc.) to the extent of 40% of their Net Bank Credit (NBC). The stipulated lending by these banks is 18% of NBC to agriculture and 10% for weaker sections, including artisans, Self Help Groups etc. Though, interest rates charged by commercial banks have been deregulated, the interest rate on loans by Commercial Banks upto Rs. 2.00 lakhs should not exceed the Benchmark Prime Lending Rate (BPLR). However, due to public perception regarding over pricing of lending to agriculture and small and medium enterprises,